PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Dainik Jagran, Delhi
Fri, 26 May 2017, Page 12
Width: 27.94 cms, Height: 21.39 cms, a3r, Ref: 35.2017-05-26.81

नमो ने रखी 'न्यू इंडिया' की नींव

सभी को साक्षर करने और सबको स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की योजनाओं पर चल रहा है काम

हरिकिशन शर्मा ● नई दिल्ली

'अच्छे दिन' के वादे पर सत्ता में आई मोदी सरकार ने बीते तीन साल में महंगाई, भ्रष्टाचार और काले धन जैसी ज्वलंत समस्याओं पर अंकुश लगाते हुए 'न्यू इंडिया' की नींव रखी है। नए इंडिया में हर महिला की रसोई में गैस कनेक्शन होगा। देश में बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ-साथ प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी।

मोदी सरकार ने 2014-17 के दौरान शुरुआती तीन वर्षों में संरचनात्मक व संस्थागत सुधारों और अनूठी पहल कर 'न्यू इंडिया' की नींव डाली है। बीमा योजनाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा का ताना-बाना बुना गया है। 'पर ड्रॉप, मोर क्रॉप' और सॉयल हेल्थकार्ड जैसी नई शुरुआत से कृषि उपज बढ़ाकर किसानों की आय दोगुनी करने का बीड़ा उठाया गया है। नौकरी की तलाश में घूम रहे लाखों युवाओं का रुख कौशल प्रशिक्षिण मुहैया कराकर स्वरोजगार की ओर मोड़ा है।

दरअसल प्रधानमंत्री ने 'न्यू इंडिया' के निर्माण का जो सपना देखा है, सरकार के विभाग भी अब उसे साकार करने में जुट गए हैं। नीति आयोग ने देश के 15 वर्षीय विजन दस्तावेज में 'न्यू इंडिया' की परिकल्पना को साकार करने का खाका भी प्रस्तुत किया है। यह ऐसा भारत होगा, जिसमें सभी के पास आवास, शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी होगी। सभी लोगों को दोपहिया वाहनों, कार और एयरकंडीशन जैसी आरामदायक सुविधाओं तक पहुंच भी होगी। सभी लोग साक्षर होंगे और सबको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही इसमें रेल और रोड का बड़ा नेटवर्क भी होगा। इसके अलावा गांवों और शहरों में सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह सब अगले 15 वर्ष में होगा।

ऐसा नहीं है कि 'न्यू इंडिया' के इस हसीन सपने को साकार करने के लिए कोई हवा में इमारत बनायी गई हो। नीति आयोग ने यह भी आकलन किया है कि यह सब हासिल करने के लिए देश को अगले 15 साल तक कम-से-कम आठ फीसद की सालाना औसत वृद्धि दर के साथ विकास करना होगा। ऐसा होने पर देश का जीडीपी 2031-32 में बढ़कर 469 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो कि 2015-16 में प्रचलित कीमतों पर 137 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह 15 साल की अवधि में जीडीपी में लगभग 332 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। इस अवधि में देश की प्रति व्यक्ति आय में भी खासी वृद्धि करना है। उम्मीद है कि 'न्यू इंड़िया' में देश का प्रति व्यक्ति जीडीपी जो कि वर्ष 2015-16 में 1,06,589 रुपये था, बढ़कर 3,14,667 रुपये हो जाएगा।

मोदी के 'न्यू इंडिया' की एक खासियत यह भी होगी कि इसमें वीआइपी कल्चर के लिए कोई जगह नहीं होगी। देश का हर नागरिक महत्वपूर्ण होगा। प्रधानमंत्री नेताओं और अफसरों की गाड़ियों से लाल बत्ती उतारने का फैसला कर इसकी शुरुआत कर चुके हैं।

प्रधानमंत्री ने इस साल अप्रैल में ऑल इंडिया रेडियो पर 'मन की बात' कार्यक्रम में इस संबंध में अपने भावों को कुछ इस तरह प्रकट किया था, 'हमें एक नया इंडिया बनाना है। इसकी अवधारणा यह है कि यहां वीआइपी की जगह ईपीआइ का महत्व बढ़े। ईपीआइ का मतलब है एवरी पर्सन इज इंपोर्टेंट। हर व्यक्ति का महत्व है।

'न्यू इंडिया' की राह में हैं कई चुनौतियां

हालांकि 'न्यू इंडिया' की राह में कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती अमीर और गरीब व्यक्तियों और संपन्न तथा अभावग्रस्त क्षेत्रों के बीच बढ़ती खाई है। बीते एक दशक में देश की विकास दर का स्तर उच्च रहा है। लेकिन, आर्थिक और क्षेत्रीय असमानताओं में कमी नहीं आई है। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल जैसे घनी आबादी वाले राज्यों में अब भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा बुनियादी सुविधाओं के लिए मोहताज है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन साधना भी चुनौतीपूर्ण होगा।